हिन्दूस्तान कॉपर लिमिटेड और अन्य

बनाम

बंशी लाल और अन्य

8 दिसम्बर, 2005

(एस.बी. सिन्हा और पी.पी. नाओलेकर, जे.जे.)

अनुबंध अधिनियम, 1872:

प्रस्ताव और स्वीकृति- कर्मचारियों को या तो वी.आर.एस. का विकल्प चुनने या किसी अन्य इकाई में स्थानांतरित होने के लिए इकाई-प्रस्ताव का समापन-वी.आर.एस. का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी बाद में उसी कर्मचारी को वापस लेने की मांग करते हैं- उच्च न्यायालय के आदेश को इस आधार पर बहाल करने की अनुमति नहीं देते हैं कि प्रस्ताव को उसकी स्वीकृति-चुनौती से पहले वापस ले लिया गया थाःएक कर्मचारी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसके द्वारा वापस लिया जा सकता है- यह योजना संविदात्मक प्रकृति की होने के कारण, भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

सेवा कानून-वी.आर.एस.- वी.आर.एस. की स्वीकृति से पहले कर्मचारी द्वारा वापस लिया गया प्रस्ताव -

अपीलार्थी-सरकारी उपक्रम की एक इकाई के बंद होने पर, उसमें काम करने वाले उत्तरदाता-कर्मचारियों को या तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने या किसी अन्य इकाई में स्थानांतरित होने की पेशकश की गई थी। उत्तरदाता-ई कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना। हालांकि, बाद में उन्होंने अपने प्रस्ताव वापस ले लिए। अपीलार्थी ने उत्तरदाताओं द्वारा भरे गए विकल्प में निहित शर्त को देखते हुए उत्तरदाताओं को वापस लेने की अनुमति नहीं दी कि एक बार प्रयोग किए गए विकल्प को वापस नहीं लिया जा सकता है। पीड़ित प्रतिवादियों ने रिट याचिका दायर की जिसे एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। डिवीजन बेंच ने की अपील को यह मानते हुए स्वीकार कर लिया कि चूंकि उत्तरदाताओं ने अपने प्रस्तावों को स्वीकार करने से पहले वापस ले लिया था, इसलिए वे पिछले वेतन के साथ बहाली के हकदार हैं।इसलिए वर्तमान अपील।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

एक कर्मचारी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले वापस लिया जा सकता था। यह योजना संविदात्मक प्रकृति की थी, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निष्कर्षों में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। हालाँकि, इसमें कोई संदेह या विवाद नहीं हो सकता है कि भले ही सेवाओं की समाप्ति इनमें उत्तरदाताओं को अवैध पाया गया था, उन्हें तब तक सेवा में बने रहने का निर्देश दिया जा सकता था जब तक कि वे अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक नहीं पहुंच जाते। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के संदर्भ में उत्तरदाताओं को पहले ही बड़ी राशि मिल चुकी है। इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा या उसकी ओर से उन्हें देय राशि को पिछले वेतन, वर्तमान वेतन या भविष्य के वेतन, यदि कोई हो, के साथ समायोजित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। अपीलार्थी उत्तरदाताओं को उन इकाइयों में स्थानांतरित करने का हकदार होगा जो ऐसे पद या पदों पर काम कर रहे हैं जो वे प्रासंगिक तिथियों पर धारण कर रहे थे।

बैंक ऑफ इंडिया और अन्य. बनाम ओ.पी. स्वर्णकुर और अन्य आदि, (2003) 2 एस.सी.सी. 721, पर निर्भर थे।

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः

सिविल अपील सं. 1807/2001

1997 के डी.बी.सी.एस.ए. 1387 में राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांकित 27.7.2000 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए देब प्रसाद मुखर्जी।

उत्तरदाताओं के लिए विजय हंसारिया, सुश्री मीनाक्षी शर्मा, कनिष्क गुप्ता और सुनील कुमार जैन।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

एस.बी. सिन्हा, जे.

अपीलार्थी भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसमें पूर्वी देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित विभिन्न तांबे की खदानें और कारखाने थे। इसकी एक खदान राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित थी जिसे 'दरीबा कॉपर प्रोजेक्ट' के नाम से जाना जाता था। यह कहा गया है कि अन्य राज्यों में स्थित खदानें बंद पड़ी हुई हैं, सिवाय मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक खदान मलिज खान के। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त दरीबा खदान को

बंद किया जाना था, बंद करने की सूचना जारी की गई थी। हालाँकि, अपीलांट कंपनी ने वर्ष 1993 में एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना भी शुरू की थी। उक्त दरीबा खदान परियोजना के कर्मचारियों से विकल्प मांगे गए थे कि क्या वे अन्य राज्यों में संचालित खदानों में स्थानांतरित होना चाहेंगे या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनेंगे। उक्त दरीबा खदान में काम करने वाले 241 कर्मचारियों में से 112 ने योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना। हालाँकि, उनमें से 10 ने बाद में अपने जी प्रस्तावों को वापस ले लिया। अपीलार्थी द्वारा उन्हें इस आधार पर ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई थी कि चूंकि विकल्पों का प्रयोग मुद्रित प्रारूप में किया गया था जिसमें एक खंड था कि एक बार प्रयोग किए गए ऐसे विकल्प को वापस नहीं लिया जा सकता था; उनके प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए थे।

अपीलार्थी के उपरोक्त रुख को ध्यान में रखते हुए, एक रिट उनके द्वारा याचिका दायर की गई थी जिसे एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। हालाँकि, दस रिट याचिकाकर्ताओं में से केवल छह व्यक्तियों द्वारा एक अंतर-

अदालत अपील दायर की गई थी। इस प्रकार, अन्य चार व्यक्तियों ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को स्वीकार कर लिया।

विवादित फैसले के कारण, राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने राय दी कि अपीलकर्ता कंपनी का रुख सही नहीं था, क्योंकि संबंधित कर्मचारियों ने अपने प्रस्तावों को स्वीकार करने से पहले वापस ले लिया था। यहाँ प्रत्यर्थियों द्वारा दायर अपील को अनुमति देते हुए, यह निर्देश दिया गया थाः

> "नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी कंपनी की सेवा में बने रहने के लिए माना जाएगा। उन्हें पिछले वेतन के साथ बहाल किया जाएगा।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री देब प्रसाद मुखर्जी ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त निर्देश जारी करने में सही नहीं था कि अपीलार्थी प्रत्यर्थियों को फिर से नियुक्त करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि एक खदान को छोड़कर अन्य सभी खदानें बंद हैं।

हमारा ध्यान इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.03.2001 के एक आदेश की ओर आकर्षित किया गया जो इस प्रकार हैः

> "छुट्टी दी जाती है। पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी। चुनौती के तहत आदेश अपील के निपटारे तक रोक रहेगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि अपीलकर्ता अपील में विफल रहते हैं तो उन्हें उत्तरदाताओं को उस अवधि के लिए पिछले वेतन सहित मजदूरी देनी होगी जिसके लिए अन्यथा वे सेवा में होते। यह प्रत्यर्थियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत लाभ प्राप्त करने से नहीं रोकता है जो इस अपील में उनकी दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा।

यह प्रस्तुत किया गया था कि उक्त आदेश के अनुसरण या उसे आगे बढ़ाने के लिए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के संदर्भ में देय राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

क्र.सं.	**नाम**	**जन्म दिनांक**	**58 वर्ष पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति की तिथि**	**वीआरएस के तहत भुगतान की गई राशि**	**राशि**

1.	बंशी लाल	05.11.43	30.11.2001	63608.20	20.4.2002
2.	ग्यारसी लाल	27.09.50	30.09.2008	173146.80	23.4.2002
3.	हरदेव	21.05.49	30.09.2007	172015.50	30.4.2002
4.	किशन लाल	26.11.50	30.11.2008	169966.00	30.4.2002
5.	नन्हूराम	26.11.52	30.11.2010	163304.10	23.4.2002
6.	चोखा राम	03.04.50	30.04.2008	178788.00	30.4.2002

की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विजय हंसारिया दूसरी ओर प्रतिवादियों ने उच्च अदालत के फैसले का समर्थन किया।

अपीलकर्ता की ओर से यहां उठाए गए तर्क के मददेनजर विकल्प फॉर्म में निहित शर्तों को कर्मचारियों द्वारा जमा किया जाना है। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प वापस नहीं लिया जा सकता है, इसका निष्कर्ष यह है कि बैंक ऑफ इंडिया और अन्य में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ का फैसलाा आदि वि. पी. स्वर्णकार और अन्य आदि, 2003 2 एससीसी 721, जिसमें यह माना गया था कि योजना प्रकति में संविदात्मक है, भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधान, 1872 लागू होगा और,

इस प्रकार, किसी कर्मचारी द्वारा दिया गया प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है उसके द्वारा इसे स्वीकार किये जाने से पहले इस प्रकार, कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निष्कर्ष हालांकि, वहां नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का संदेह या विवाद होने पर भी उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी यहां उत्तरदाताओं को अवैध पाया गया, वे हो सकते हैं होने का निर्देश दिया वे तब तक सेवा में बने रहे जब तक वे अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक नहीं पहुंच गए प्रतिवादी संख्या 1, बंशी लाल, पहले ही अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच चुके थे हालांकि, जहां तक अन्य उत्तरदाताओं का सवाल है वे सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने के हकदार हैं।

हालांकि, इसमें कोई विवाद नहीं है कि उन्हें बडी रकम मिली है। दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की शर्तें इस न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता द्वारा या उसकी ओर से उन्हें देय राशि इस प्रकार, वर्तमान बकाया वेतन की रकम के साथ समायोजित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए मजदूरी या भविष्य की मजदूरी, यदि कोई हो।

अपीलार्थी प्रत्यर्थियों को खदानों में स्थानांतरित करने का हकदार होगा जो ऐसे पद या पदों पर काम कर रहे हैं जो वे संबंधित तिथियों पर धारण कर रहे थे। यदि यह पाया जाता है कि अपीलार्थी ने उक्त कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान किया है, तो यह स्पष्ट किया जाता है कि उन्हें देय भविष्य के वेतन को उस राशि से समायोजित किया जाएगा जो उन्हें पहले ही प्राप्त हो चुकी थी।

प्रत्यर्थियों को स्थानांतरित स्थानों पर अपने पदों पर तुरंत शामिल होने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन अपीलार्थी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें इस संबंध में किए गए संचार की तारीख से 15 दिनों के बाद नहीं।

इस अपील का निपटारा उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ किया जाता है। कोई लागत नहीं।

डी.जी.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।